In respect of a few items the export figures for 1982-83 and 1983-84 are also available as shown below:—

Value Rs. lakhs

Item/Group of items	1982-83	1983-84(P)
Rice	19941	12283
Wheat	—	129
Fish and fish preparations	34865	32247
Meat and meat preparations	8011	6247
Sugar and sugar preparations	5646	13695
Tea	36462	50085
Cotton fabrics	26427	27097

(P) Provisional and subject to revision.
Source: DGCI and S, Calcutta.

राजधानी चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड

1478. **श्री राम नरेश कुशवाहा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, दरीबा कलां तथा निशाद चिट फण्ड, दिल्ली एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा चलाई जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि सदस्यों को 8 हजार रुपए की चिट वैल्यू है परन्तु वास्तव में उन्हें केवल 5,200 रुपए लाभांश के रूप में काट लिए जाते हैं और उस राशि को सदस्यों में नहीं बांटा जाता है;

(ग) फरवरी, 1982 तक उक्त चिट फण्ड ने कितने सदस्यों को पूरे 8,000 रुपए का ऋण दिया है और कितने सदस्यों को केवल केवल 5,200 रुपए दिए हैं; और

(घ) क्या उक्त चिट फण्ड कम्पनियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कारवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त ब्यौरे के अनुसार सूचना इस प्रकार है :—

निशाद चिट फण्ड, दिल्ली के नाम से प्रशासन के पास ऐसी कोई कम्पनी रजिस्टर्ड नहीं की गयी है ।

1964 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर यथाविस्तारित मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार चिट श्रृंखलाओं में बोलियों के आधार पर चिटों के मूल्यों के 40 प्रतिशत तक लाभांश की अनुमति है जिसमें कम्पनी के फोरमैन को 5 प्रतिशत कमीशन भी शामिल है । राजधानी चिट फण्ड प्रा. लि., ने 8,000 रुपए के मूल्य वर्ग की केवल एक चिट श्रृंखला चलाई थी जिसके अप्रैल 1981 से जुलाई 1984 तक की अवधि के दौरान 40 महीनों के लिए 40 अभिदाता थे। इस श्रृंखला में कम्पनी के फोरमैन को 5 प्रतिशत कमीशन सहित 35 प्रतिशत लाभांश दिया गया था । इस प्रकार 8,000 रुपए की चिट मूल्यों के मामले में, इनाम पाने वालों को 5,200 रुपए की पेशकश की गयी और बाकी रकम कम्पनी के फोरमैन की 5 प्रतिशत काटने के बाद सभी अभिदाताओं के बीच लाभांश के रूप में बांट दी गयी ।

फरवरी 1982 तक इनाम पाने वाले 10 अभिदाताओं को 5,200 रुपए की दर से अदायगी की गयी। ये अदायगीयां अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की गयी ।

चिट फण्ड रजिस्ट्रार, दिल्ली को राजधानी चिट फण्ड प्रा. लि. के खिलाफ अनियमितताओं की 4 शिकायतें प्राप्त हुई थीं । उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई की गयी है ।

Central team to arrange bulk purchases of handicraft items from Jammu and Kashmir

1479. SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Jammu and Kashmir has approaches the Central Government to send a team of officers to the State to arrange bulk purchases of handicraft items as was done a few years ago; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) A letter has been received from the Government

of J and K requesting for assistance from the Government of India and its agencies in providing marketing support to the artisans of the State.

Loans for setting up Spinning Mills in Bihar

1480. SHRI SURAJ PRASAD:
SHRI INDRADEEP SINHA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three spinning mills are being set up in Bihar on the turn-key basis;

(b) whether it is also a fact that the construction work of these mills has since been completed;

(c) whether it is also a fact that term loans required for these mills have not yet been granted by the Industrial Development Bank of India and National Co-operative Development Corporation; and

(d) if so, by when the loans are likely to be granted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) Yes, Sir.

(b) The Civil construction work is in progress.

(c) and (d) The National Cooperative Development Cooperation has under a Central Sector Scheme for Handloom Weavers Cooperative Spinning Mills, sanctioned a loan assistance of Rs. 896.807 lakhs for helping the State of Bihar to take part in the share capital of these mills and has already reimbursed an amount of Rs. 199.23 lakhs to the State Government. The Industrial Development Bank of India have sanctioned assistance or two of these units.

Hike in Defence expenditure by Pakistan

1481. SHRI NARENDRA SINGH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported hike in defence expenditure by about 20 per cent by Pakistan in their budget for 1984-85; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) The Government have seen media reports to the effect that Pakistan has made a substantial increase in its defence budget this year. No confirmed information in this regard is, however, available.

(b) Our plans for defence preparedness are periodically updated taking into consideration all factors having on our security.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा एक फर्म पर छापा

1482. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मई के पहले सप्ताह में रेफ्रिजरेटरों और एअर कंडीशनरों के फालतू पुर्जों की निर्माता एक फर्म के परिसर पर छापा मार कर करीब 1.29 करोड़ रुपये की उत्पादशुल्क की चोरी का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1983-84 में इस फर्म से अब तक कितने रूपए की शुल्क राशि वसूल की गई है ; और

(घ) उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने के लिए फर्म के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एम. कृष्णा): (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि जनवरी, 1984 में मैसर्स फ्रीजकिंग इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लि., नई दिल्ली के परिसर पर मारे गये छापों के बारे में प्रश्न पूछा गया है । यह आरोप लगाया गया है कि प्रशीतकों और वातानुकूलकों के फालतू पुर्जे बनाने वाले उक्त निर्माता ने उत्पादन शुल्कय माल का न्यून मूल्यांकन किया है । पिछले